

श्रमाधारस

EXTRAORDINARY

भाग **II**--न्तर 3--उप-वरह (ij

PART II—Section 3—Sub-section (3)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 505] नर्द बिल्ली, बुधवार, नव-बर 29, 1972/प्रप्रहाउँगा 8, 1894 No. 505) NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 1972/AGRAHAYANA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं ितससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सर्व । Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th November 1972

S.O. 727(E)/18A/IDRA/72.—Whereas the Central Government is of the opinion that Messrs. Containers and Closures, Limited, Calcutta, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in expresse of the powers conferred by section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta (here nafter referred to as "Authorised Controller") to take over the management of the whole of the said undertaking, namely Messrs. Containers and Closures, Limited Calcutta, subject to the following terms and conditions, namely:—

- (i) The Authorised Controller sha'l comply with all directions issued from time to time by the Central Government.
- (ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the official Gazette of this Order.
- (iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier, if it considers it necessary to do so.
- 2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the official Gazette.

[No. F. 2/17/72-CUC.]

K S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

ग्रौद्योगिक विकास मंत्रालय (ग्रौद्यौगिक विकास विभाग)

त्रादेश

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1972

का॰ ग्रा॰ 7.7(ग्र)/18र/माई डी ग्रांप /ए72-प्तः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मैसर्स कन्टनस एंड कलोजर्स लिमिटेड, कलकत्ता ग्रौद्योगिक उपक्रत का प्रबंध जिसकी बाद्धत उद्योग (विकास ग्रोप विनिथमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के प्रधीन अन्वेषण किया गया है, इस प्रकार किया जा रहा है, जो लोक हित में श्रतिग्रहितकर है ;

अत: अब, उक्त श्रधिनियम की धारा 18 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इंडस्ट्रियल रिकन्सट्रक्शन कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता को (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकृत नियंत्रक" कहा गया है), उक्त सम्पूर्ण उपक्रम अर्थात् मैं सर्स कन्टेनर्स एड क्लोजर्स लिमिटेड, कलकत्ता, का निम्नलिखित निबन्धनों और शतौं के अधीन रहते हुए, प्रबन्ध यहण करने के लिए, एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात्:——

- (i) प्राधिकृत नियंत्रक केन्द्रीय सरकार द्वारा ममय-समय पर जारी किए गए सभी निदेशों का श्रनुपालन करेगा।
- (ii) प्राधिकृत नियंत्रक इन ग्रादेश के राज्यत में प्रकाशन की नारीख से पांच वर्ष के लिए पदधारण करेगा !
- (iii) केन्द्रीय गरकार, यदि वह ऐसा करना भ्रावश्यक समझती है तो, प्राधिश्वत नियंत्रक की निय्क्रिस को पहले भी समाप्त कर सकेगी ।
 - 2 यह श्रादेण, राज्यत्र में प्रकाणन की तारीख में पांच वर्ष की श्रवधि तक प्रभावी रहेगा।

[नं०फा० 2/17/72-र्मा यूर्मा]

के० एउ० भटनागर, पंपुक्त सचिव ।